What is the budget?

The plan of earning and expenditure for the coming year is called budget. In the case of the domestic budget, it is prepared according to the household's needs and income, while in the case of the country or state budget, it is prepared according to the income and expenditure.

बजट क्या होता है?

आने वाले वर्ष के लिए कमाई और खर्चे की योजना को ही बजट कहते हैं। घरेलू बजट के मामले में यह घरेलू जरूरतों और आमदनी के हिसाब से बनाया जाता है, जबकि देश या राज्य

The Central Government, i.e. the Government of India, presents the general budget before every financial year. Prior to 2017, it has been offered in late February. But from the year 2017 it is being introduced on 1 February. Now since it is the budget of the central government, it contains an estimate of the total receipts and total expenses of the central government.

केंद्र सरकार, यानी भारत सरकार, हर वित्तीय वर्ष (Financial Year) के पहले आम बजट (general budget) पेश करती है। 2017 के पहले, यह फरवरी के अंत में पेश होता रहा है। लेकिन वर्ष 2017 से यह 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है। अब चूंकि यह केंद्र सरकार का बजट होता है, इसलिए इसमें केंद्र

Why the need for budget?

This whole exercise is needed so that the country's economy can be kept on track. Because if there is no plan for income and expenses, then it is possible that the expenses may become much more than the income. If this happens, the country's economy can reach on the verge of shutdown.

बजट की जरूरत क्यों?

इस सारी कवायद (exercise) की जरूरत इसलिए पड़ती है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था (economy) को पटरी पर रखा जा सके। क्योंकि अगर **आमदनी** और खर्च की कोई योजना नहीं होगी, तो संभव है कि खर्चे, आमदनी के के मुकाबले बहुत ज्यादा भी हो जाएं। ऐसा हुआ तो, देश की अर्थव्यवस्था ठप (shutdown) होने के कगार पर पहुंच सकता है।

Budget Formulation:

The Government of India has two budgets – the Railway Budget and the General Budget. In 1921, on the recommendation of the Acworth Committee, the railway budget was separated from the budget. The Railway Budget contains estimates of expenditure and receipts only of the Ministry of Railways, while the General Budget contains estimates of expenditure and receipts of all Ministries of the Government of India (except Railways).

बजट निर्माण :

भारत सरकार के दो बजट हैं- रेलवे बजट और आम बजट। 1921 में आकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को बजट से अलग कर दिया गया था। रेल बजट में केवल रेल मंत्रालय के खर्चों और आमदनी के अनुमान होते हैं जबकि आम बजट में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों (रेल के अलावा) के व्यय और प्राप्तियों के।

The following agencies are involved in budget formulation:

Ministry of Finance – It has the overall responsibility of making the budget and provides the required leadership and direction. Administrative Ministry - They have detailed knowledge of administrative needs.

Planning Commission - It works to include the priorities of the plan in the budget. In other words, the Ministry of Finance maintains close liaison with the Planning Commission for the inclusion of plan priorities in the budget. Comptroller and Auditor General - It provides accounting skills required for preparation of budget estimates.

बजट निर्माण में निम्नलिखित एजेंसियाँ शामिल होती हैं:

वित्त मंत्रालय- बजट बनाने की पूरी जिम्मेदारी इसकी है और यह अपेक्षित नेतृत्व एवं दिशा प्रदान करता है । प्रशासनिक मंत्रालय- इनको प्रशासनिक आवश्यकताओं का विस्तृत ज्ञान होता है ।

योजना आयोग- यह बजट में योजना की प्राथमिकताओं को शामिल कराने का काम करता है । दूसरे शब्दों में, बजट में योजना की प्राथमिकताओं को सम्मिलित कराने के लिए वित्त मंत्रालय योजना

The various stages of budget preparation are as follows:

Preparation of Estimates by Drawing & Disbursing Officers:

5-6 months before the commencement of the financial year, ie in September-October, the Ministry of Finance sends circulars and forms to the Administrative Ministry seeking estimates of the expenditure for the coming financial year. Administrative Ministries forward these forms on their behalf to the local/regional authorities ie Disbursing Officers.

बजट निर्माण के विभिन्न चरण निम्न हैं:

आहरण एवं संवितरण (Drawing & Disbursing) अधिकारियों द्वारा अनुमानों की तैयारी:

वित्त वर्ष प्रारंभ होने से 5-6 महीने पहले अर्थात सितंबर-अक्टूबर में वित्त मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय को परिपत्र और प्रपत्र भेजकर उससे आगामी वित्त वर्ष के खर्चों के अनुमान माँगता है। प्रशासनिक मंत्रालय इन प्रपत्रों को अपनी ओर से स्थानीय/क्षेत्रीय अधिकारियों अर्थात

कैसे पास होता है बजट

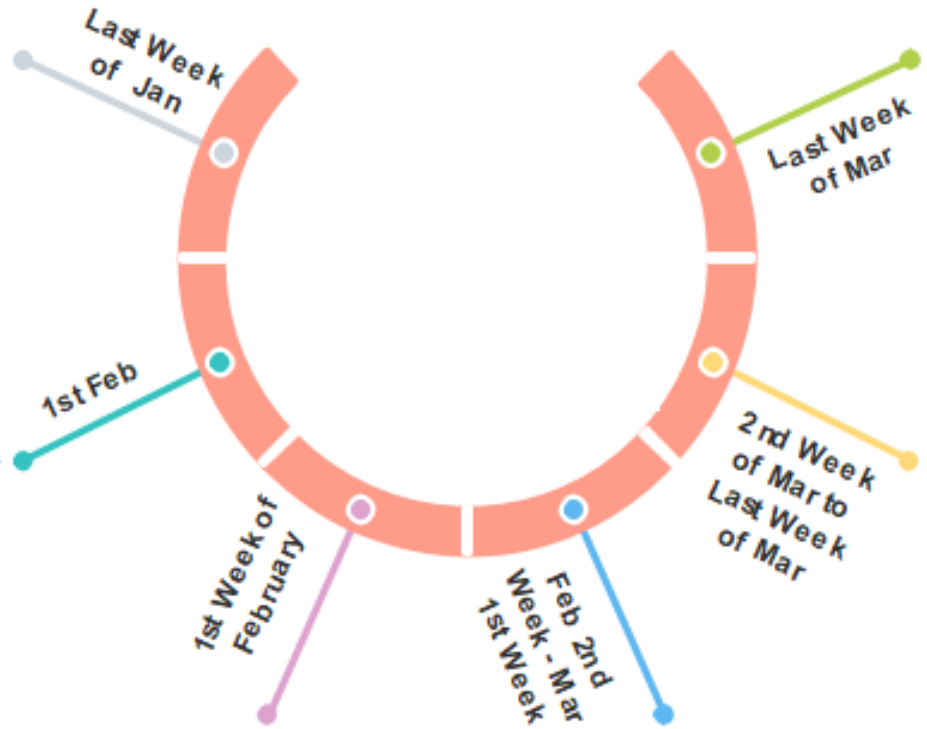

सत्र की शुरुआत

आर्थिक सर्वेक्षण पेश

बजट पेश

- वित्त मंत्री का बजट भाषण
- वित्त विधेयक पेश किया जाता है

सामान्य चर्चा

बजट प्रस्तावों पर सांसद चर्चा करते हैं

समिति का विमर्श

- स्थायी समिति बजट प्रस्तावों पर विचार करती है
- संसद स्थगित रहती है

गहन चर्चा

बजट प्रस्तावों पर सिलसिलेवार गहन चर्चा

बजट को मंजूरी

लोकसभा से वित्त विधेयक पास और राष्ट्रपति की मंजूरी

Beginning of budget session:

There are three sessions of the Parliament in a year. First budget, second monsoon and third winter session. The longest and most intensive session in these three sessions is the Budget session.

The budget session is divided into two phases. The first phase is of only 8-10 days while the second phase is of 4-5 weeks. There is a recess of one month between these two phases the budget session begins in the last week of January. It continues till the second week of April. There is no fixed date for it to start or end.

बजट सत्र की शुरुआत:

संसद में साल में तीन सत्र होते हैं। पहला बजट, दूसरा मॉनसून और तीसरा शीत सत्र। इन तीनों सत्र में सबसे लंबा और सघन सत्र Budget sessionही होता है।

बजट सत्र दो चरणों में बंटा होता है। पहला चरण सिर्फ 8-10 दिन का होता है जबकि दूसरा चरण 4-5 weeks का होता है। इन दोनों phases के बीच एक महीने का अवकाश (Recess) होता है।

बजट सत्र की शुरुआत जनवरी के आखिरी हफ्ते में होती है । ये अप्रैल के

बजट के प्रकार (Types of Budget)

1. पारम्परिक या आम बजट (Aam Budget)
2. शून्य आधारित बजट (Zero Based Budget)
3. निष्पादन बजट (Performance Budget)
4. लैंगिक बजट (Gender Budget)
5. परिणामोन्मुखी बजट (Outcome Budget)

आम बजट	अंतरिम बजट	पूरक बजट
पूरे साल के लिए	कुछ महीनों के लिए बनता है	बचे हुए वक्त के लिए बजट
हर साल का नियमित बजट	सरकार बदलने के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है	अतिरिक्त पैसे की जरूरत होने पर
सरकार बड़े फैसले लेती है	सरकार बड़े फैसलों से बचती है	सरकार सिर्फ जरूरी फैसले लेती है

1. Traditional or General Budget:

The initial form of "General Budget" of the present time is called "Traditional Budget". The main objective of the general budget is to establish "financial control" over "legislature" and "executive". In this budget, the income and expenditure of the government is accounted for. In this budget, the government mentions how much money will be spent in which sector in the next financial year.

1. पारम्परिक या आम बजट:

वर्तमान समय के “आम बजट” का प्रारंभिक स्वरूप “पारम्परिक बजट (Traditional Budget) कहलाता है| आम बजट का मुख्य उद्देश्य “विधयिका” और “कार्यपालिका” पर “वित्तीय नियंत्रण” स्थापित करना है| इस बजट में सरकार की आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है| इस बजट में सरकार अगले वित्त वर्ष में किस क्षेत्र में कितना धन खर्च करेगी, उसका उल्लेख करती है|

2. Zero Based Budget:

In zero-based budgeting, each work is determined on "zero base", that is, new expenditure is not determined on the basis of old expenditure, but new policy-making is done for each work.

This budget is also called "sun set budget", which means that before the end of the financial year, each department has to present a zero-based budget, in which every activity of the department is accounted for.|

2. शून्य आधारित बजट:

शून्य आधारित बजट में प्रत्येक कार्य का निर्धारण “शून्य आधार” पर किया जाता है अर्थात पुराने व्यय के आधार पर नए व्यय का निर्धारण नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक कार्य के लिए नए सिरे से नीति-निर्धारण किया जाता है|

इस बजट को “सूर्य अस्त बजट (sun set budget)” भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले प्रत्येक विभाग को शून्य आधारित बजट पेश करना पड़ता है, जिसमें विभाग के

3. Performance Budget:

The budget prepared on the basis of the results of a work is called "Performance Budget". The first "Performance Budgeting" in the world was started in the United States of America.

In America, in 1949, "Hopper Commission" was formed for administrative reforms. Based on the recommendation of this commission, "Performance Budgeting" was started in America. What is the government doing for the betterment of the public in the "Performance Budget"? How much are you doing? And at what cost? All things like that are included in it.

"Performance Budget" is also called Achievement Budget or Performance Budget.

3. निष्पादन बजट:

किसी कार्य के परिणामों का आधार मानकर बनाए जाने वाले बजट को "निष्पादन बजट (Performance Budget)" कहते हैं| विश्व में सर्वप्रथम निष्पादन बजट की शुरूआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी|

अमेरिका में 1949 में प्रशासनिक सुधारों के लिए "हूपर आयोग" का गठन किया गया था| इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर अमेरिका में "निष्पादन बजट" की शुरूआत हुई थी| "निष्पादन बजट" में सरकार जनता की भलाई के लिए क्या कर रही है? कितना कर रही है? और किस कीमत पर कर रही है?, जैसी सभी बातों को

4. Gender Budget:

In a budget, the expenditure incurred on all those schemes and programs, which are related to the welfare of women and children, it is considered as Gender Budget. Through the gender budget, the government makes a provision to ensure a fixed amount every year for schemes and programs related to the development, welfare and empowerment of women.

4.लैंगिक बजट:

किसी बजट में उन तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों पर किया गया खर्च, जिनका संबंध महिला और शिशु कल्याण से होता है, उसका उल्लेख लैंगिक बजट (Gender Budget) माना जाता है| लैंगिक बजट के माध्यम से सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान करती है|

5. Result oriented budget

Every year a large number of development related schemes like MNREGA, NRHM, Mid Day Meal Scheme, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Digital India, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana etc. are started in India. A huge amount of money is spent every year in these schemes. But, to what extent these schemes were successful in achieving their goal, there is no specific scale set in our country to evaluate it. Sometimes the cost increases manifold due to the hanging of the schemes. Therefore, in order to remove these shortcomings, for the first time in India in 2005, "Outcome Budget" was introduced, under which it was necessary to give details of how the funds allocated in the general budget were used by various ministries and departments.

The result-oriented budget serves as a yardstick for the

5.परिणामोन्मुखी बजट:

भारत में हर वर्ष बड़ी संख्या में विकास से संबंधित योजनाएं, जैसे- मनरेगा, एनआरएचएम, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि शुरू होती हैं| इन योजनाओं में हर वर्ष भारी-भरकम धनराशि खर्च की जाती है| लेकिन, ये योजनाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहां तक सफल रहीं, इसके मूल्यांकन के लिए हमारे देश में कोई खास पैमाना निर्धारित नहीं है| कई बार योजनाओं के लटके रहने से लागत में कई गुना की बढ़ोतरी हो जाती है|

अतः इन कमियों को दूर करने के लिए 2005 में भारत में पहली बार "परिणामोन्मुखी बजट (Outcome Budget)" पेश किया गया था, जिसके अंतर्गत आम बजट में आवंटित धनराशि का विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों ने किस प्रकार उपयोग किया उसका ब्यौरा देना आवश्यक था.

परिणामोन्मुखी बजट (Outcome Budget) सभी मंत्रालयों और विभागों के कार्य प्रदर्शन के लिए एक मापक का कार्य करता है, जिससे सेवा, निर्माण प्रक्रिया, कार्यक्रमों के मूल्यांकन और परिणामों को और